HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4857/2008

National Insurance Company Limited, Divisional Office-I, Panch Batti, M.I. Road, Jaipur Through Senior Divisional Manager.

----Appellant

Versus

1. Ramkishore Meena S/o Shri Mannaram Meena, R/o Village Kharad, Tehsil Jamva-Ramgarh, District Jaipur.
2. Prahlad Narayan Meena S/o Shri Maliram Alias Maniram, R/o Village Chota Rohda Va Khurd, Tehsil And District Dausa.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. V.P. Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	None present

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/02/2026

अपीलार्थी–बीमा कम्पनी की ओर से यह अपील धारा 30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे ''अधिनियम–1923'' कहा जावेगा) के तहत विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा प्रकरण W.C.C.N.F. No. 256/2006 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2008 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से दावेदारों को कुल 2,58,336/– रूपये मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रतिकर दिलाया है।

प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कम्पनी का निवेदन है कि कथित दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के करीब तीन माह पश्चात दर्ज करायी गयी है, अतः घटना घटित होना संदेहास्पद है। यह भी निवेदन किया कि आहत प्रत्यर्थी क्रम–2 के यहां नियोजित हो, यह तथ्य भी समुचित रूप से प्रमाणित नहीं है, साथ ही जिस जीप को दुर्घटना में अन्तर्वलित होना बताया

है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार ''अधिनियम–1923'' की धारा–30 के प्रावधानों के अनुसार विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होने पर ही अपील पोषणीय है, उक्त निर्णय के सुसंगत पैरा संख्या–9, 10, 11 तथा 12 निम्नानुसार है–

> **9.** At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.
>
> **10.** The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.
>
> **11.** The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.
>
> **12.** In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court

to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

वर्तमान मामले में विद्वान अधिवक्ता–बीमा कम्पनी की ओर से तीन आपत्तियां उठायी हैं, उनके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरान्त निर्णय पारित किया है, उपरोक्त निर्णय उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया गया हो अथवा जो तथ्य अभिलेख पर थे ही नहीं, उन पर विचार करने के उपरान्त मनमाना निर्णय दिया हो, ऐसी स्थिति अभिलेख पर नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, इस प्रकार न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था तथा अधिनियम–1923 की धारा–30 के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2008 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं, स्थगन प्रार्थना पत्र यदि लंबित है तो वह भी उक्त प्रकार से अस्वीकार किया जाता है।

विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /15